

एक जुलाई से शुरू हो चुके हैं आवेदन

बैंकिंग में एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा, आईआईटी दिल्ली-नेटवेस्ट ने शुरू किया प्रोग्राम

नई दिल्ली, एजेंसी। आने वाले वर्षों में बैंकिंग की तस्वीर केवल मोबाइल ऐप, एटीएम या आनलाइन लेनदेन से नहीं बदलेगी, बल्कि इसकी नई दिशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप आधारित नवाचार तय करेंगे। इसी सोच को साकार करने के लिए नेटकवेस्ट ग्रुप और आइआइटी दिल्ली के फाउंडेशन फार इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (फिट) ने नेटकवेस्ट फिन्टेक फ्रंटियर प्रोग्राम (एनएफएफपी) की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य विश्वविद्यालयों में हो रहे शोध को सीधे बैंकिंग उद्योग की जरूरतों से जोड़ते हुए प्रयोगशाला से बाजार तक पहुंचाना है।

भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत होगा तकनीकी सहयोग- शनिवार को आइआइटी दिल्ली में अनावरण किए गए इस कार्यक्रम के तहत संस्थान के शोधकर्ता, फैकल्टी और स्टार्टअप्स नेटकवेस्ट ग्रुप की वास्तविक बैंकिंग चुनौतियों पर काम करेंगे। एआइ, डिजिटल बैंकिंग, साइबर सुरक्षा, डिजिटल ट्रस्ट और क्वांटम तकनीक जैसे क्षेत्रों में ऐसे समाधान विकसित किए जाएंगे, जिन्हें सीधे बैंकिंग सेवाओं में लागू किया जा सके। कार्यक्रम भारत और ब्रिटेन के बीच तकनीकी सहयोग को भी नई मजबूती देगा। कार्यक्रम दो प्रमुख ट्रैक में संचालित होगा। रिसर्च ट्रांसलेशन ट्रैक के तहत आइआइटी दिल्ली के शोध समूह बैंकिंग क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं और डेटा पर शोध करेंगे। वहीं स्टार्टअप इनोवेशन ट्रैक के माध्यम से टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल (टीआरएल) 8 वाले स्टार्टअप्स को अपने उत्पादों का परीक्षण, पायलट प्रोजेक्ट और



व्यावसायिक विस्तार का अवसर मिलेगा। सफल नवाचारों को पेटेंट के साथ ब्रिटेन के बैंकिंग बाजार तक पहुंचाने में भी सहयोग दिया जाएगा। नेटकवेस्ट ग्रुप की कंट्री हेड (भारत) और सीओओ रूचिका पनेसर ने

कहा कि भविष्य की बैंकिंग मजबूत इनोवेशन इकोसिस्टम पर आधारित होगी, जहां उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षण संस्थान मिलकर वास्तविक समस्याओं के समाधान तैयार करेंगे। वहीं आइआइटी दिल्ली के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी ने कहा कि यह साझेदारी संस्थान की शोध क्षमता को वैश्विक बैंकिंग उद्योग की जरूरतों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। इससे भारतीय स्टार्टअप्स को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी तकनीक प्रदर्शित करने और वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने का अवसर मिलेगा।

दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तीन शूटर गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। बाहरी दिल्ली में रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े तीन शूटरों को गिरफ्तार किया है। इनमें से दो आजमगढ़ और एक दिल्ली का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार, पकड़े गए तीनों शूटर दिल्ली में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में जुटे थे और टारगेट किलिंग की साजिश रच रहे थे। लेकिन इसी दौरान रोहिणी जिला पुलिस को उनके मूवमेंट के बारे में जानकारी मिली और उन्हें दबोच लिया गया। पुलिस का दावा है, इन शूटरों की गतिविधियों के बारे में खुफिया सूचना मिली थी और इसके बाद स्पेशल स्टाफ ने उन्हें ट्रैक करना शुरू कर दिया। फिर बाद में निगरानी और तकनीकी जांच के आधार पर तीनों को दबोच लिया गया। पुलिस से बताया कि इन शूटर्स को विदेश में बैठे नेटवर्क के जरिए जानकारी मिल रही थी।

18 गलियां जलमग्न, 300 से ज्यादा घरों में घुसा पानी; किराड़ी के सूरत विहार में बाढ़ जैसा हालात

नई दिल्ली, एजेंसी। किराड़ी की शर्मा कालोनी के बाद अब सूरत विहार कालोनी में जलभराव ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। कालोनी की 23 गलियों में से 18 गलियां जलमग्न हैं, इन गलियों में लगभग 700 मकानों में से 300 से अधिक घरों में एक से तीन फीट तक पानी भरा हुआ है। घर में पानी घुसने के कारण 30-40 परिवार पलायन कर अन्य क्षेत्रों में चले गए। मंगलवार को हुई वर्षा के बाद सूरत विहार पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। कालोनी की मुख्य सड़कों से लेकर गलियों व घरों तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पांच दिनों से कालोनीवासियों का रहना मुश्किल हो चुका है। जलभराव के कारण कालोनी में प्रवेश व निकास के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। स्कूल न जा पाने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

कालोनी नीचे होने के कारण ठप पड़ी जलनिकासी

मुबारकपुर रोड के निर्माण के बाद कालोनी का लेवल लगभग एक फीट से अधिक नीचे होने के कारण जलनिकासी ठप पड़ चुकी है। दूसरी ओर कालोनी के साथ खाली मैदान घरों का पानी निकल जाया करता था। लेकिन डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) के खाली जमीन पर लैंडफिल साइट के कचरे से भराव के दिया गया। ऐसे में कालोनी का पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कालोनी की अधिकतर गलियों में पानी भरा है और 50 प्रतिशत घरों में पानी भर गया है। जलनिकासी का कोई साधन नहीं है। गंदे पानी की वजह चर्मरोग फैल रहा है। कालोनी में रहने वाले नारकीय जीवन जी रहे हैं।

मोबाइल कंपनी से जुड़े थे जान गंवाने वाले 15 लोग

हनुई, एजेंसी। वियतनाम में एक द्वीप से वापस लौट रही एक नाव समंदर में पलट गई, इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई है। अधिकारियों के अनुसार, नाव में 32 भारतीय पर्यटक और चार क्रू मेंबर सवार थे। जानकारी के अनुसार, थाईलैंड की खाड़ी में स्थित 'फू क्वोक' वियतनाम के सबसे लोकप्रिय बीच डेस्टिनेशन में से एक है। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास शनिवार को हुए दर्दनाक नाव हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। हादसे के प्रत्यक्षदर्शी और आंध्र प्रदेश के गुंटूर निवासी आशीष कुमार ने बताया कि स्प्रीडबोट द्वीप से केवल 300-400 मीटर ही आगे बढ़ी थी, तभी अचानक

पलट गई। आशीष कुमार ने पीटीआई से फोन पर बातचीत में बताया कि वह मोबाइल कंपनी लावा इंटरनेशनल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर, विक्रेता और कर्मचारी घूमने के लिए 9 जुलाई को वियतनाम पहुंचे थे और रविवार को भारत लौटने वाले थे। उन्होंने बताया कि पर्यटकों को तीन अलग-अलग नावों में बैठाकर द्वीप तक ले जाया गया था। हादसे के समय 32 भारतीय पर्यटकों वाली एक नाव दूसरे द्वीप के लिए खाना होई थी, जबकि बाकी दो नावों के यात्री हनु में रुट नगोआई द्वीप पर फोटो खिंचवा रहे थे। आशीष के मुताबिक, स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 1:30 बजे नाव



ने द्वीप से मुश्किल से 300-400 मीटर की दूरी तय की थी कि वह अचानक पलट गई। उन्होंने कहा, 'हम फोटो खींच रहे थे। कुछ समझ पाते, उससे पहले ही नाव पलट गई। हम सभी मदद के लिए चिल्लाते लगे।' उन्होंने बताया कि उस समय मौसम ज्यादा खराब नहीं था। थोड़ी हवा चल रही थी, लेकिन किसी द्वीप पर

यह सामान्य बात है। आशीष ने दावा किया कि बचाव दल जल्दी मौके पर पहुंच गया और घायलों व शवों को किनारे ले आया, लेकिन शुरूआत में वहां मेडिकल टीम मौजूद नहीं थी। उन्होंने कहा, 'सीपीआर देने के लिए भी कोई चिकित्सा टीम तुरंत नहीं थी। हम सभी अभी भी सदमे में हैं।' उन्होंने बताया कि वह अकेले यात्रा कर रहे थे, लेकिन कई लोग अपने परिवार के साथ आए थे। उनके एक परिचित डिस्ट्रीब्यूटर अपनी पत्नी के साथ उसी नाव में थे। हादसे में उनकी पत्नी की मौत हो गई, जबकि वह अस्पताल में जिंदगी और मौत से जुझ रहे हैं। इस हादसे के बाद सभी बचे हुए पर्यटकों को होटल वापस ले जाया गया।

वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हुन ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने केंद्र और स्थानीय अधिकारियों से राहत और बचाव अभियान तेज करने, घायलों का बेहतर इलाज कराने और मृतकों के परिवारों की हर संभव मदद करने को कहा है। वियतनाम के मुंबई स्थित महावाणिज्य दूतावास ने बयान जारी कर हादसे पर गहरा दुख जताया। और कहा कि इस मुश्किल समय में उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को हादसे के कारणों की पूरी जांच करने, सुरक्षा व्यवस्था में हुई किसी भी कमी का पता लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

यमुना सफाई में जनता की होगी भागीदारी, दिल्ली में डीडीए शुरू करेगा 'यमुना संवाद'

नई दिल्ली, एजेंसी। यमुना की सफाई में आम नागरिकों को भागीदार बनाने पर बल दिया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

इसी कड़ी में दिल्ली विकास प्राधिकरण यमुना संवाद कार्यक्रम के माध्यम से दिल्लीवासियों और विशेषज्ञों का सुझाव लेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। यमुना संवाद शुरू करने से पहले कार्यशाला आयोजित की जा रही है।

इस वर्ष सितंबर और अगले वर्ष जनवरी में यमुना संवाद के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे, जिसमें व्यापक विचार-विमर्श कर रोडमैप को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं, इसकी तैयारी के लिए कार्यशाला आयोजित की जा रही है। पहली कार्यशाला में सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि, पर्यावरण विशेषज्ञ, विज्ञानिक, शहरी नियोजक, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, तकनीकी संस्थानों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हूँ। उन्होंने बाढ़ के मैदान के अनुकूल योजना और घाटों के विकास पर चर्चा की।

इस तरह के आधारभूत ढांचा के निर्माण पर बल दिया गया जो प्राकृतिक बाढ़ चक्र से



तालमेल बिठा सकें। साथ ही पर्यावरण के अनुकूल घाट निर्माण पर बल दिया। जल्द ही प्रकृति-आधारित समाधान, जल गुणवत्ता और जल निकासी, वित्तपोषण मॉडल और शासन जैसे विषयों पर दो और हितधारक कार्यशालाएं आयोजित होंगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संभू यमुना बाढ़ क्षेत्रों का दौरा

करने के बाद डीडीए अधिकारियों के साथ बैठक कर दिल्ली के निवासियों को विशेषज्ञों

दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा पर एएसआई का फोकस, बारिश में हादसे रोकने के लिए कड़े इंतजाम

नई दिल्ली, एजेंसी। मानसून के मौसम को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने दिल्ली मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी 174 संरक्षित स्मारकों के रखरखाव और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश जारी किए हैं।

दिल्ली मंडल ने सभी स्मारकों के प्रभारियों को मानसून के दौरान नियमित निरीक्षण, जलभराव रोकने, साफ-सफाई और संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। इसका उद्देश्य वर्षा के कारण ऐतिहासिक धरोहरों को होने वाले नुकसान को रोकना और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

पर्यटकों की आवाजाही नियंत्रित करने के निर्देश एएसआई ने विशेष रूप से उन स्मारकों या उनके हिस्सों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा है, जो जर्जर स्थिति में हैं। ऐसे स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों की

तैनाती करने और पर्यटकों की आवाजाही नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारियों को कहा गया है कि किसी भी खतरे की स्थिति में तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। साथ ही वर्षा के दौरान नियमित निगरानी और मरम्मत संबंधी आवश्यक कार्यों की रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी।

एएसआई के अनुसार दिल्ली में जिन स्मारकों या उनके हिस्सों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, उनमें प्रमुख रूप से शामिल क ो ट ल फिरोजशाह का शाही महल वाला भाग, बेगमपुरी मस्जिद, महरोली के स्थित बहादुर शाह का जफर महल, पुराना किला के मुख्य द्वार की ऊपरी मंजिल के आसपास का जर्जर हिस्सा आदि शामिल हैं। इन स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के साथ पर्यटकों को जोखिम वाले क्षेत्रों से दूर रखने की व्यवस्था की गई है।



पीओके के बढ़ते विरोध ने पाकिस्तान के कश्मीर दावे पर उठाए सवाल: रिपोर्ट में दावा- लोग अब खुलकर उठा रहे हैं आवाज

न्यूयॉर्क, एजेंसी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में जारी विरोध प्रदर्शनों ने पाकिस्तान के उस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें वह खुद को कश्मीरी मुसलमानों का प्रतिनिधि बताता रहा है। न्यूयॉर्क स्थित थिंक टैंक गेटस्टोन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीओके में लोग अब पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं और इससे पाकिस्तान की कश्मीर संबंधी कहानी कमजोर पड़ती दिख रही है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान लोगों ने 'फोसेज आउट' (पाकिस्तानी सेना बाहर जाओ) जैसे नारे लगाए। इससे साफ संकेत मिलता है कि वहां के लोगों में पाकिस्तान की नीतियों को लेकर नाराजगी बढ़ रही है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि यह आंदोलन मई 2023 में बिजली की बढ़ती कीमतों और आटे की कमी के विरोध से शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व जॉइंट अवंामी एक्शन कमिटी ने किया, जिसमें व्यापारी, वकील, ट्रांसपोर्ट, छत्र और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल थे। कमिटी ने सरकार के सामने 38 सूत्रीय मांगपत्र रखा था। इसमें सस्ती बिजली, सस्ता आटा, जरूरी सामान पर सब्सिडी और स्थानीय चुनाव व्यवस्था में सुधार जैसी मांगें शामिल थीं।

रिपोर्ट के मुताबिक, लोगों का कहना है कि पीओके में बड़ी मात्रा में जलविद्युत उत्पादन होता है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें महंगी बिजली दी जा रही है। वहीं खाद्य पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और जरूरी सामान की कमी भी बनी

हुई है। इन समस्याओं के कारण लोगों में लंबे समय से नाराजगी थी, जो अब बढ़े आंदोलन का रूप ले चुकी है।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जून 2026



में मुजफ्फराबाद और रावलकोट जैसे प्रमुख शहरों में पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। इसमें कई लोगों की मौत और कई अन्य घायल हुए। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने 5 जून को अवंामी एक्शन कमिटी पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया। इसके नेताओं पर देशद्रोह के मामले दर्ज किए गए। साथ ही इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गईं तथा अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। रिपोर्ट में कहा गया है

कि पीओके में मुस्लिम समुदाय द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन यह दिखाते हैं कि वहां के लोग अब पाकिस्तान को अपना रक्षक नहीं मानते। कई लोग मानते हैं कि पाकिस्तान के बिना उनका

भविष्य बेहतर हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लोगों को राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अवसर और विकास के मामले में पीओके के लोगों की तुलना में बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। गेटस्टोन इंस्टीट्यूट का कहना है कि पीओके में चल रहा यह आंदोलन पाकिस्तान की कश्मीर नीति और उसके लंबे समय से किए जा रहे दावों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

अमेरिका ने फिर शुरू किए हमले: बमबारी से दहला ईरान, होर्मुज में जहाज पर आईआरजीसी के हमले का बताया जवाब

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने बताया कि अमेरिकी सेना ने आज शाम 7:15 बजे (ईटी) ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। यह इस सप्ताह ईरान के खिलाफ हमलों का तीसरा दौर है। ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति और कमांडर-इन-चीफ डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए जा रहे हैं। सेंटकॉम के अनुसार, यह कार्रवाई ईरान की इस्लामिक रिवालयुशनरी गार्ड कोर्प्स (आईआरजीसी) की तरफ से एक वाणिज्यिक जहाज पर किए गए हमले के जवाब में की गई है। ईरान की सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले एक कंटेनर जहाज 'एम/वी जीएफएस गैलेवसी' पर हमला किया था। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जारी एक बयान में बताया कि इस हमले के बाद जहाज का एक नागरिक चालक दल सदस्य लापता है। जहाज में आग लगने और उसके इंजन रूम को भारी नुकसान पहुंचने के कारण वह आगे की यात्रा करने में असमर्थ है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान में कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, कश्म द्वीप पर विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं।

संपादकीय

जांच होती है, रिपोर्ट आती है...फिर हादसे क्यों नहीं रुकते?



कि जिन लापरवाहियों या खामियों की वजह से वे भयावह हादसे हुए, उनकी जांच करने और नियमों

का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी थी? कायदे से इसके लिए उन सरकारी

महकमों और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जिनका दायित्व है कि वे समय-समय पर इमारतों में अग्निशमन से लेकर बचाव इंतजामों की जांच करें। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और लखनऊ में आग लगने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को नगर निकायों को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन न करने वाले शीर्ष अधिकारी अब व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। अदालत की यह टिप्पणी बेहद अहम है कि हादसों के बाद सिर्फ भवन निर्माताओं को गिरफ्तार किया जाता है, जबकि घटना वाले क्षेत्र के अधिकारियों को छोड़ दिया जाता है।

यह छिपा नहीं है कि किसी इमारत में आग लगने की वजह से अगर लोग मारे जाते हैं, तो उसकी मुख्य वजह बचाव के इंतजामों को ताक

पर ख देना होती है। मसलन, अचानक आग लगने की स्थिति में उसे बुझाने या उससे बचने के लिए वैकल्पिक निकास की ठोस व्यवस्था न होना लोगों की जान जाने की सबसे बड़ी वजह होती है। आजकल कई इमारतों में सुरक्षा के आधुनिक इंटजाम के नाम पर 'डिजिटल दरवाजे' लगा दिए जाते हैं, जो हादसे की स्थिति में काम करना बंद कर देते हैं और उसमें लोग फंसे कर मारे जाते हैं।

सवाल है कि अग्निशमन से लेकर बचाव के तमाम उपायों को सख्ती से लागू कराना किसकी जिम्मेदारी है। इसलिए यह बिल्कुल उचित सवाल है कि केवल इमारतों के मालिकों या प्रबंधकों को कठघरे में खड़ा करना काफी नहीं है, बल्कि हादसे की मुख्य जड़ यानी संबंधित महकमे और शीर्ष अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी का इलाज करना जरूरी है।

पहली ही बारिश में थम गई दिल्ली, आखिर हर साल क्यों दोहराती है वही कहानी?

दिल्ली की एक प्रमुख सड़क पर भारी बारिश के बाद घट्टनों तक जलभराव है। सड़क पर कारें, बसें, ऑटो-रिक्शा और मोटरसाइकिलें ट्रैफिक में फंसी हैं, जबकि एक व्यक्ति छत्ता लेकर पानी के बीच से गुजर रहा है। पृष्ठभूमि में आधुनिक इमारतें, ओवरपास, घने काले बादल और बारिश के बीच चमकती इमरजेंसी लाइटें दिखाई दे रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते अमूमन यह माना जाता है कि दिल्ली में समुची व्यवस्था अन्य शहरों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होगी। सरकार और स्थानीय प्रशासन के दावों में भी यही झलकता है, लेकिन चिंता की बात यह है कि जब हकीकत सामने आती है, तब भी उसमें सुधार सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहता है। इसका एक प्रमुख उदाहरण है बारिश के दिनों में दिल्ली की रफ्तार थम जाना। हर साल राजधानी के बाशिंदों को जलभराव और यातायात अवरुद्ध हो जाने की वजह से ट्रिंकटों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में समग्र विकास के आश्वासनों के साथ सत्ता परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन समस्याओं का संजाल अभी भी कमोबेश वैसा ही बना हुआ है। यही वजह है कि बीते गुरुवार को मानसून की पहली तेज बारिश में ही कई जगह सड़कें तालाब बन गईं, यातायात ठप हो गया और लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। सवाल है



कि बरसात से पहले संबंधित महकमों की ओर से जिन पूर्व तैयारियों का भरोसा दिलाया जाता है, वे समय आने पर कहाँ गायब हो जाते हैं! कहने को राष्ट्रीय राजधानी में हर साल मानसून के आगमन से काफी पहले समस्याओं से निपटने की औपचारिक तैयारी शुरू हो जाती है। इसके तहत मुख्य रूप से छोटे-बड़े नालों और सड़क किनारें जलनिकासी के लिए बनी नालियों की सफाई करनी होती है। मगर इन तैयारियों का अधिकांश कार्य कागजों तक ही सीमित रहता है। जाहिर है कि सरकार का जोर व्यवस्था को सुधारने पर कम और दावों पर ज्यादा रहता है। यह बात भी छिपी नहीं है कि दिल्ली में जलभराव की समस्या पर सियासत भी खूब होती है। इस बात भी सत्ता पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि पिछली सरकार के कार्यकाल के मुकाबले जलभराव का संकेत काफी कम हुआ है। वहीं, विपक्ष का कहना है कि दो-तीन चिह्नित स्थलों को छोड़कर बाकी जगह का हाल जस का तस बना हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार तुलनात्मक सुधार का हवाला देकर अपनी पीठ थपथपाने के बजाय समस्या की गंभीरता पर ध्यान केंद्रित करे और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, ताकि लोगों को बारिश में किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े।

आज का कार्टून



नीति आयोग की रिपोर्ट: झारखंड में प्राथमिक स्कूलों का ड्रॉपआउट शून्य

विकसित भारत का निर्माण केवल आर्थिक प्रगति से नहीं होगा। इसके लिए शिक्षित, कुशल, संवेदनशील और जागरूक नागरिकों का निर्माण आवश्यक है। प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक अभिभावक और पूरे समाज को यह संकल्प लेना होगा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। झारखंड ने यह सिद्ध कर दिया है कि बीच में स्कूल छोड़ने की दर को शून्य करना कोई असंभव लक्ष्य नहीं है। यह उपलब्धि पूरा देश हासिल कर सकता है। अब समय आ गया है कि 'हर बच्चा विद्यालय में, हर बच्चा शिक्षा में और कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं' केवल एक नारा न रहकर राष्ट्रीय संकल्प बने।

राजेंद्र जोशी

किसी भी राष्ट्र के विकास की सबसे मजबूत नींव उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब देश का प्रत्येक बच्चा विद्यालय तक पहुंचे, नियमित रूप से अध्ययन करे और अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करे। इसलिए अब केवल सौ फीसद नामांकन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सौ फीसद ठहराव और शून्य 'ड्रॉपआउट' यानी बीच में एक भी बच्चा स्कूल न छोड़े, इसे राष्ट्रीय लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। हाल ही में नीति आयोग द्वारा भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर जारी रिपोर्ट में झारखंड से एक अत्यंत उत्साहजनक समाचार सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014-15 में झारखंड में प्राथमिक स्तर पर 'ड्रॉपआउट' दर 6.41 फीसद थी, जो वर्ष 2024-25 में घटकर शून्य हो गई है। इसी प्रकार माध्यमिक स्तर पर यह दर 23.2 फीसद से घटकर केवल 3.5 फीसद रह गई है। यह उपलब्धि केवल झारखंड की नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का विषय है। इससे यह सिद्ध होता है कि अगर सरकार, प्रशासन, विद्यालय और समाज मिलकर योजनाबद्ध ढंग से कार्य करें, तो बीच में स्कूल छोड़ने जैसी गंभीर समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भी प्रत्येक बच्चे

को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा उसे विद्यालय में बनाए रखने पर विशेष बल देती है। इसके बावजूद देश के सामने आज भी विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की समस्या गंभीर बनी हुई है। अगर सकल नामांकन अनुपात यानी जीईआर के आंकड़ों पर दृष्टि डालें, तो यह चिंता और बढ़ जाती है। कक्षा छह से आठ तक जीईआर लगभग 90.9 फीसद है, जबकि कक्षा नौ-दस में यह घटकर 79.3 फीसद रह जाता है। कक्षा 11-12 तक पहुंचते-पहुंचते यह केवल 56.5 फीसद रह जाता है। स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में बच्चे, विशेष रूप से कक्षा आठ के बाद शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं। यह स्थिति शिक्षा के साथ-साथ देश के सामाजिक और आर्थिक विकास से भी सीधे जुड़ी हुई है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सहित विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि बच्चों के स्कूल छोड़ने के अनेक कारण हैं। गरीबी, बाल श्रम, बाल विवाह, प्रवासी मजदूर परिवारों का लगातार स्थान परिवर्तन, विद्यालयों की दूरी, आधारभूत सुविधाओं का अभाव, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी और शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव इसके प्रमुख कारण हैं। झारखंड की सफलता यह संदेश देती है कि अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और सामाजिक सहभागिता साथ आए तो परिवर्तन

संभव है। आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित उन सभी राज्यों में विशेष अभियान चलाए जाएं, जहां विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या अभी भी चिंताजनक है। बीच में स्कूली पढ़ाई



छोड़ने की समस्या पर काबू पाने के लिए सबसे पहले विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करना होगा। प्रत्येक बच्चे के लिए पूर्ण-प्राथमिक से कक्षा बारह तक सुरक्षित, आकर्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। सरकारी विद्यालयों की विश्वसनीयता को फिर से स्थापित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। विद्यालयों में पर्याप्त कक्षाएं, प्रशिक्षित शिक्षक, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, अलग शौचालय तथा डिजिटल संसाधनों की

उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। जहां विद्यालय नहीं हैं, वहां नए विद्यालय स्थापित किए जाएं और आवश्यकता के अनुसार छात्रावासों का निर्माण किया जाए। विशेष रूप से बालिकाओं के लिए सुरक्षित छात्रावास और सुगम परिवहन की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अनेक बालिकाएं केवल दूरी और सुरक्षा के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं।

प्रवासी मजदूरों के बच्चों की शिक्षा भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे बच्चों के लिए वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र, लचीली अध्ययन व्यवस्था तथा सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता है। स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय समाज की भागीदारी से ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से फिर जोड़ा जा सकता है। नामांकन के बावजूद कोई बच्चा लगातार अनुपस्थित रहता है, तो उसके अभिभावकों से संपर्क करके विद्यालय छोड़ने के कारणों का समाधान खोजना चाहिए। अगर किसी कारणवश कोई बच्चा विद्यालय छोड़ देता है, तो उसकी वापसी भी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं, सेतु

पाठ्यक्रम तथा अतिरिक्त अध्ययन की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे वे बिना किसी संकोच के फिर अपनी कक्षा के अनुरूप अध्ययन प्रारंभ कर सकें। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों के लिए विशेष प्रयास आवश्यक हैं। ऐसे क्षेत्रों में सामुदायिक साक्षरता केंद्र, लचीले समय की अध्ययन कक्षाएं तथा विशेष शिक्षण केंद्र संचालित किए जा सकते हैं, जहां बच्चे अपनी परिस्थितियों के अनुसार पढ़ाई जारी रख सकें। इससे उनका विद्यालय से संबंध बना रहेगा और भविष्य में उनकी नियमित शिक्षा भी बाधित नहीं होगी। विकसित भारत का निर्माण केवल आर्थिक प्रगति से नहीं होगा। इसके लिए शिक्षित, कुशल, संवेदनशील और जागरूक नागरिकों का निर्माण आवश्यक है। प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक अभिभावक और पूरे समाज को यह संकल्प लेना होगा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। झारखंड ने यह सिद्ध कर दिया है कि बीच में स्कूल छोड़ने की दर को शून्य करना कोई असंभव लक्ष्य नहीं है। यह उपलब्धि पूरा देश हासिल कर सकता है। अब समय आ गया है कि 'हर बच्चा विद्यालय में, हर बच्चा शिक्षा में और कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं' केवल एक नारा न रहकर राष्ट्रीय संकल्प बने। विकसित भारत की यात्रा का सबसे सशक्त आधार यही होगा।

